IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत के दृष्टी से एक राष्ट्र एक चुनाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रा·डॉ·लक्षटे रत्नाकर बाबुराव
विभागाध्यक्ष तथा सहयोगी प्राध्यापक
स्नातक एंव स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग
देगलूर महाविद्यालय देगलूर

सारांश *(Abstract)* : यह शोध लेख एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत मे किस प्रकार आवश्यक है इसके विश्लेषण से संबंधित है · एक राष्ट्र एक चुनाव से जो पैसा , समय , साधनसंपत्ती बचेगी उसका सदुपयोग राष्ट्र को विकसित बनाने मे होगा · सुशासन का निर्माण होगा , युवा किस प्रकार अपने भविष्य के प्रती सोचेंगे , सामाजिक और पर्यावरणीय प्रद्रूषण घटेगा और एक राष्ट्र एक चुनाव से सरकारी मशनरी का ध्यान विकास कार्यो मे लगेगा , जिससे विकास कार्य कि गती बढेगी इन सब का विश्लेषण इसमे किया है · साथ हि इस विषय पर वर्तमान केंद्र सरकार कि क्या सोच है इसे भी स्पष्ट किया है · इस विचार को वास्तविकता मे लाने हेतू क्या करना होगा यह भी जानकारी दी है ·

कीवर्ड : एक राष्ट्र एक चुनाव , लोकतंत्र ,चुनाव आयोग, राजनीतिक दल , लोकसभा ,विधानसभा ·अलोकतांत्रिक , राजनीति ,विचार , निरंतर चुनाव

1. प्रस्तावना :

एक राष्ट्र एक चुनाव यह विचार लोकसभा और सभी राज्यो के विधानसभा के चुनावो को पांच साल मे एक बार हि करणे का समर्थन करता है· इससे भारत कि साधन संपत्ती , मनुष्यबळ आदि का जो निरंतर चुनाव मे अपव्यय होता है वह नही होगा ·भारत मे पहला आम चुनाव 1952 को हुवा · तबसे ले के आजतक के लोकसभा चुनावो पर एक नजर डालने से इन सभी चुनाव मे होनेवाले अलोकतांत्रिक , असंवैधानिक , अमानविय कवायतो पर नजर डालने से सभी को एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार अच्छा महसुस होता है ·

वर्तमान भारत के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पूर्णतः नया विचार नही है ·क्योंकी आजादी के बाद 04 आम चुनाव को भारत ने सफल बनाया है · इन चार आम चुनाव मे लोकसभा समेत सभी राज्यो के चुनावो को बिना ब्रेक के हर पांच साल के बाद पूर्ण किया है · वर्तमान भाजपा कि स्पष्ट जनमत कि सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे मे सकारात्मक सोच रही है · लेकीन इसको राजनीति का स्वरूप प्राप्त हुवा है · जिन्होने आजादी के बाद दो दशक एक राष्ट्र एक चुनाव को कार्यान्वित किया है वह आज इसके विपक्ष मे बोल रहे है ·

1967 के बाद भारत कि राजनीति मे आमुलचूल परिवर्तन हुए·इन राजनीतिक –सामाजिक-आर्थिक बदलावो ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओ के एकत्रित चुनाव कि प्रक्रिया को खंडित किया · क्योंकी देश के अनेक राज्यो के विधानसभाओ को भंग कर वहा मध्यावती चुनाव कराए · जिसकारण आज हर साल मे चार से पांच राज्यो के विधानसभा चुनाव होते है · राजनीतिक दलो के प्रत्याशी अपने राजनीतिक स्वार्थवाद को पूर्ण करने हेतू दल –बदल को अपनाते है ·जिससे पुन्हा उन्ही सीटो पर मध्यावधी चुनाव होते है · इन चुनावो मे केंद्र –राज्यो कि प्रशासनिक यंत्रणा , चुनाव आयोग , उनके कर्मचारी सभी चुनावी कवायतो मे व्यस्त रहते है · इस व्यस्तता से देश के राजनीतिक- प्रशासनिक – सामाजिक –आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सभी अंगो को निजात दिलाने हेतू एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार सामने आया है ·जो निरंतर चुनाव से होनेवाले गंभीर परिणामो का प्रतिवाद है

इस शोध लेख मे एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत कि दृष्टी से क्यो उपयुक्त है , यह स्पष्ट किया है · पिछले सात दशको मे भारत ने अनेक क्षेत्रो मे विशाल प्रगति कि है ·फीर भी वर्तमान भारत मे जो समस्या आजादी के काल मे थी वह आज भी है · आज भी चुनावो मे भ्रष्टाचार ,फर्जी वोट , बूथ कब्जा , पैसो कि लेनदेन, प्रत्याशीयो कि खरेदी होती है · चुनाव भ्रष्टाचार का सही मार्ग बन गया है · स्वास्थ , शिक्षा , सडक , नदियो के जोड , बिजली कि आपूर्ती आदि मे भारत आज भी पिछडा है , जिसे कोविड -19 की सर्वव्यापी महामारी ने उजागर कर दिया है · राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र मे कार्यरत व्यक्ती के क्षमता का सही इस्तमाल नही होता है · राजनेता एंव उच्च पदस्थ अधिकारी कर्मचारी के प्रतिभा को चुनाव या अपने निजी कामो मे अधिक इस्तमाल करते दिखाई देते है · प्रशासनिक सुधार हेतू आयोग तो निर्माण होते है ,लेकीन उनके क्रियान्वयन को राजनीतिक या चुनावी रंग मे रंग दिया जाता है · चुनावी सुधार अपने स्वार्थ या फायदे के हिसाब से अपनाये जाते है · लोकतंत्र रहकर भी चुनावी सुधार से संबंधित जनमत को अनदेखा किया जाता है · भारत उपरी सभी स्थिती और अन्य क्षेत्रो मे सुधार करणे हेतू एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार फायदेमंद साबित होगा · लेकीन इसे कार्यान्वित करने से पूर्व संवैधानिक धारा और ढाचे के बारे मे भी विचार करना जरुरी है ·

2. एक राष्ट्र एक चुनाव कि भारत की दृष्टीसे आवश्यकता :

एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार मूलगामी है · इससे भारत के किन क्षेत्रो मे क्या बदलाव होगे यह अध्ययन का विषय है · इसी विचार को आधार मानकर शोधार्थी ने इस लेख मे एक राष्ट्र एक चुनाव कि आवश्यकता को निम्न प्रकार से दर्शया है ·

A. अर्थव्यवस्था मे सुधार होगा :

किसी भी राष्ट्र को विकसित बनणे हेतू आर्थिक पहेलु पे अधिक काम करना होगा · भारत ने आजादी से हि आर्थिक सुधारो पे अधिक ध्यान दिया है · लेकीन बढती जनसंख्या , निरंतर चुनाव , भ्रष्टाचार , नैसर्गिक - मानव निर्मित आपदा , आतंकवाद आदि अर्थव्यवस्था के विकास मे प्रमुख बाधाए है · इनमे निरंतर चुनाव अर्थव्यवस्था के विकास मे बाधा है इसको अनेक विद्वतजनो ने स्पष्ट किया है · इस पर अनेक विद्वत , ज्ञानी पंडीतो मे मतभेद हो सकते है · क्योंकी चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक मजबूत करते है ·उसके हेतू कूच धन राशी खर्च होती है तो कूच फरक नही पडेगा · यह बात भी सही है · लेकीन यही चुनाव अगर एक साल मे पांच बार , हर माह मे होणे लगे तो चुनाव एक मजाक बन जाते है ·इसके प्रति कि गंभीरता , संवेदनशीलता , आत्मीयता खत्म हो जाती है · वह महज एक औपचारीक प्रक्रिया बन जाति है · निरंतर चुनाव से देश के अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोजा बढ जाता है · यह कम करने के बारे मे सोचना सभी भारतीयो का कर्तव्य है ·चुनाव कराणे मे राजनीतिक दल , चुनावी प्रत्याशी , कार्पोरेट जगत , भारत सरकार आदि का मिलाकर अरबो रुपयो का खर्च होता है· इस खर्चे मे निरंतर चुनाव से अधिक बढोतरी होती है ·जिस देश मे आजभी कुल जनसंख्या से 80 % जनता गरिबी रेखा के निचे है ? सभी लोगो को शिक्षा जैसी मुलभूत सुविधा मुहवय्या होती नही · पक्की सडके , बिजली , रोजगार के साधनो कि आपूर्ती का अभाव है ·उधोग , तंत्रज्ञान , तकनिकी के लिए हम दुसरे देशो पे निर्भर है · उस देश मे निरंतर चुनाव करना जरुरी है क्या ? मेक इन इंडिया , आत्मनिर्भर भारत , कुशल भारत -कौशल्य भारत , नदी जोड प्रकल्प , कोरोना जैसे महामारी का सामना करणे मे निर्माण आर्थिक कठीनाईयो को देखकर हमे एक राष्ट्र एक चुनाव को कार्यान्वित करना चाहिए· क्योंकी इन निरंतर के चुनावो मे खर्च होनेवाला पैसा हम आर्थिक -सामाजिक विकास पर खर्च कर देश को आर्थिक बलशाली बना सकते है · जिससे हम विकसित राष्ट्र बनेगे · हमारे आंतरराष्ट्रीय हेतू भी जल्द पुरे होंगे·स्थिर सरकार के कारण निवेश भी बढेगा · अर्थव्यवस्था मे सुधार हेतू एक राष्ट्र एक चुनाव बुष्ट का काम करेगा ·

B. प्रभावकारी सुशासन हेतू आवश्यक :

किसी भी देश कि व्यवस्था का प्रशासनिक व्यवस्था महत्वपूर्ण अंग है · यह यंत्रणा जितनी कारगर होगी उतनी हि राष्ट्र और जन कल्याण कि नीति अधिक गती से कार्यन्वित होगी · इसके लिये जरुरी है कि उन्हे उनके हि कार्य मे व्यस्त रखे और उन्हे अधिक प्रशिक्षित बनाये ·प्रभावकारी सुशासन निर्माण करने कि जिम्मेवारी इन्ही के कंधो पे होती है · क्योंकी इनका सीधा संबंध योजना , नीति के क्रियान्वयन से होता है ·भारत जैसे विशाल प्रशासनिक यंत्रणा , कार्यक्षेत्र , योजना के देश मे प्रशासन का सुशासन होना अधिक आवश्यक है · इसके हेतू देश मे अनेक प्रयास भी किये है ·फिरभी सुशासन नही है · सुशासन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक उदेश है · इस उदेश के पूर्ती हेतू एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार , नीति कारगर साबित होगी ऐसा मानने वाला एक वर्ग है · यह वर्ग ना केवल राजनीतिक है , बल्की प्रशासनिक भी है · ऐसा इस अध्ययन से स्पष्ट होता है · अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी , कर्मचारीओ का कहना है की , प्रशासनिक व्यवस्था का अपने नियत कार्य से ध्यान हटाने मे चुनाव का सबसे बडा योगदान है ·वह भी खासकर निरंतर होनेवाले चुनाव · निरंतर चुनाव से देश कि संपूर्ण प्रशासनिक यंत्रणा चुनावी कामो मे व्यस्त रहती है · चुनाव कि गतिविधिया एक -दो दिन मे खत्म होनेवाली नही है · वह महिनो चलती है · जिससे हमारे अधिकतर कर्मचारी चुनावी कार्यो मे व्यस्त रहते है , जैसेकी वोटर लिस्ट को बनाना , उसे अपडेट करना ,

चुनावी प्रशिक्षण देना /लेना ,चुनाव से संबंधित सभी साधनो या साहित्य कि जमावट करना , मतदान जागृती से संबंधित उपक्रम चलाना , चुनाव के लिए आवश्यक कर्मचारी कि जोड करना आदि कार्य करणे मे हि कर्मचारी व्यस्त रहते है ·अब तक हुए इस अध्ययन से यह बात सामने आई है कि केंद्र और राज्यो के चुनाव मे कर्मचारी एक साल से काम पे लाग जाते है · हालाकि सभी जिलाधिकारी कार्यालयो मे अलग से चुनावी कार्यालय , उसका प्रशासनिक उपजिलाधिकारी पद का अधिकारी और उसके अधीन अन्य कर्मचारी रहते है · लेकीन लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव इन अधिकारी और कर्मचारी से हि पूर्ण नही होते ·इसमे उस जिले के सभी महसुल , पोलीस, शिक्षा , कृषी ,स्वास्थ ,बांधकाम ,मिलिट्री आदि विभाग के कर्मचारी ,अधिकारी ,जवान आदि का सहयोग आवश्यक है ·देश या राज्य के सभी विभाग के कर्मचारी , अधिकारी हमेशा हि चुनावी गतीविधियो मे व्यस्त रहने लगे तो प्रशासनिक कार्य जो जनहित , लोककल्याण , राष्ट्र हित से जुडा है वह आगे कैसे बढेगे · प्रशासन जवाबदेही ,उत्तरदायी , साफ -सुथरा · कार्यप्रवण, गतिमान नही बनेगा · इसलिये एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार आवश्यक है ·

C. विकास कार्यो कि गती बढाने मे सहाय्यभूत *:*

क्या चुनाव और विकास का कोई संबंध है *?* निरंतर चुनाव से विकास कि प्रक्रिया अवरुद्ध होती है *?* पांच साल मे एक बार चुनाव होणे से विकास कार्य कि गती सचमुच बढेगी *?* क्या निरंतर चुनाव से नियत प्रशासनिक कार्य बाधित होता है *?* ऐसे कई अन्य सवाल एक राष्ट्र एक चुनाव और विकास का संबंध जोडणे से निर्माण होते है · चुनाव पारदर्शक ,निष्पक्ष और लोकतांत्रिक गरिमा को संभालकर हो इसलिए आचारसंहिता होती है · चुनाव के दौरान राजनेता , राजनीतिक दल या प्रत्याशी कि ओर से मतदाता को लुभाने जन्य कोई आचरण न हो इस हेतू से आचारसंहिता होती है · एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करनेवालो का कहना है कि , निरंतर चुनाव के कारण देश , राज्य, विभाग , जिला , तालुका , मंडळ आदि मे आचारसंहिता होणे से विकास कार्य रुक जाते है · याने चुनाव किसीभी नई परियोजना , योजना, नीति निर्धारण पर रोक लगाता है · महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य मे 2016-17 मे साल के 365 दिनो मे से 325 दिन चुनावी आचारसंहिता थी· यह आचारसंहिता राज्य कार्यपालिका , स्थानीय निकाय के चुनाव के कारण थी· ऐसे स्थिती मे सर्वसमावेशक विकास से संबंधित कार्य कि गती थम जाती है· यह बात सभी राजनेता और राजनीतिक दलो के प्रतिनिधी भी जानते है · फिरभी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आढ मे रहकर विरोध हो रहा है · एक राष्ट्र एक चुनाव से आचारसंहिता कि प्रक्रिया से प्रशासन , प्रशासनिक कर्मचारी ,राज्यव्यवस्था और आम आदमी को छुटकारा मिलेगा · जिससे सभी एक होकर देश के प्रशांसनिक एंव अन्य विकास से संबंधित कार्यो कि गती को बढाने मे जूट जायेंगे

D. सरकारी मशनरी का सामाजिक कल्याण कि ओर लक्ष केंद्रित होगा

सरकारी मशनरी के सहायता से हि चुनाव सफल होते है · पहले हि सरकारी मशनरी पर दिन ब दिन काम का बोज बड रहा है· क्योंकी जनसंख्या मे हर दस साल मे लक्षणीय बधोत्तारी हो रही है · सूचना अधिकार , सूचना प्रोदोगीकी ने जनता को अधिक सजग बनाया है · सरकार से जनता कि अपेक्षा बढ रही है · आपदा मे बढोतरी हो रही है · कोरोना , बाढ आदि ने सरकारी मशनरी के कार्यो मे बढोतरी कि है · इन्ही कामो के लिए सरकारी मशनरी को समय कम मिलता है · उपरसे सरकारी मशनरी मे होनेवाली कर्मचारी कि भरती (सभी क्षेत्र)का प्रमाण भी घट रहा है · ऐसे मे काम अधिक ओर कर्मचारी कम यह स्थिती सरकारी मशनरी कि बनी है · ऐसेमे चुनाव का अतिरिक्त काम इसी सरकारी मशनरी को करना पडता है ·अगर चुनाव पांच साल मे एक बार होते है तो ठीक है · इसकेलिए नियत काम का सही व्यवस्थापन कर समय निकाला जाता है · लेकीन देश के हर राज्य मे चुनावी स्थिती दिन ब दिन बिघड रही है · एक साल मे स्थानीय निकाय (गरम पंचायत, पंचायत समिती , जिला परिषद), पतसंस्था , दुध मंडळ · कामगार संघटना , शिक्षक कर्मचारी संघ ,जिला समिती आदि के चुनाव निरंतर होते है ·इसके अलावा राज्य विधानसभा , विधानपरिषद के नियत चुनाव , दल -बदल , मृत्यू के कारण होणे वाले मध्यावधी चुनाव आदि के कारण राज्य ओर देश हमेशा चुनाव के मोड मे होता है · यह चुनावी मोड देश के सभी वर्गो को अलोकतांत्रिक कवयतो कि तरफ ले जाता है · राजनीति का अपराधीकरण , भ्रष्टाचार बढता है · पुलिस, न्यायालय , शिक्षा विभाग , सभी प्रशासनिक विभाग , जिसे हम सरकारी मशनरी का अहम ओर महत्वपूर्ण हिस्सा मानते है वह सभी अपने नियत काम मे समय नही दे पाते है · सरकारी कचेरी , न्यायालय मे फाईलो का ढीग बढ रहा है · खासकर शिक्षा विभाग और प्रशासनिक यंत्रणा जिनका अधिक संबंध सामाजिक कल्याण से वह अपने लक्ष से भटक जाते है, ऐसा इस अध्ययन मे स्पष्ट हुआ है· सरकारी मशनरी का जन कल्याण कि ओर ध्यान आकर्षित करना अति आवश्यक है · इसलिए जिन कारणो से उनका ध्यान अपने लक्ष से हट जाता है उन अनेक कारणो मे से निरंतर चुनाव यह एक कारण है ·ईन कारणो को जल्द हि मुलता नष्ट करना सरकार मे शामिल सभी का काम है ·या ऐसे कारणो से सरकारी मशनरी का

सामाजिक कल्याण से अपना ध्यान किस प्रकार विचलित होता है यह सरकार को बताना पंडित ,विद्वत जणो का भी काम है ·देश के लोकसभा , विधानसभा या यु कहे सभी क्षेत्र मे होणे वाले चुनाव पांच साल मे एक बार हि होते है · तो यह देश मे मूलगामी बदलाव होगा · सभी का ध्यान चुनाव के बाद समाज और राष्ट्र हित कि ओर अधिक आकर्षित होगा · सरकारी मशनरी को चुनाव मुक्त बनाने का समय आया है ·

E. युवा अपने भविष्य के प्रती सोचेगा :

भारत दुनिया का दुसरे नंबर का जनसंख्यावाला देश है · इस जनसंख्या मे सबसे अधिक संख्या युवा वर्ग कि है · युवा वर्ग का राजनीति मे एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है ·जो आजादी के आंदोलन से लेके हाल हि मे हुए लोकपाल आंदोलन तक · आज हर वर्ग का युवा राजनीति मे अपना करियर करणे के प्रति आकर्षित है · लेकीन भारत कि राजनीति कुछ चुनिदा घराणो के हातो और उनके हित मे व्यस्त है · इसलिए देश के राजनीति मे घराणेशाही मजबूत है · साथ हि राजनीतिक दल सत्ता कि बागडोर युवा वर्ग के हाथो मे न देकर बुजुर्ग राजनेता के हाथ मे सोपते है · हाल हि मे राजस्थान के राजनीति मे जो भूचाल उमडकर सामने आया उसके पिचे युवा नेतृत्व की होनेवाली अवहेलना है· चुनाव मे उन्ही युवा को राजनीतिक दल प्रत्याशी बनाते है जिनको कोई राजनीतिक पाठबळ हो· सभी राजनीतिक दल अपने बेटे , बहु , पत्नी , दामाद ,भाई आदि को हि चुनाव मे अवसर देते है · राजनीतिक दलो को बढा करणे मे आम जनता का अधिक योगदान होता है · लेकीन जब दल का नेता चुनना , चुनाव मे टिकट देणे कि बात आती है तब आम कार्यकर्ता को दूर कर अपने परिवार के सदस्य को चुना जाता है· साथ हि निरंतर चुनाव होणे से अधिकतर युवा चुनावी गतीविधियो मे व्यस्त रहते है · राजनीतिक दलो का प्रचार करना · पर्चे बाटना ,चुनावी रयालीओ का आयोजन करना, प्रचार हेतू घर से बाहर रहना ,प्रतिपक्ष के प्रत्याशी से झगडे करना , पुलिस थाने के चक्कर लगाना ,राजनीतिक अपराधीकरण का हिस्सा बनाना ·इस कारण वह अपने व्यक्तिगत करीयर कि ओर ध्यान नही देते · जिसकारण उनके घर वाले हमेशा हि चिंतीत रहते है ·निरंतर चुनाव उन्हे अपने भविष्य के बारे मे सोचने का समय हि नही देते · सभी राजनेता चुनाव के समय इन युवा वर्ग का इस्तमाल करते है · उनके हित के बारे मे बडी बडी घोषणा करते है· रोजगार ,शिक्षा , स्वावलंबन , आत्मनिर्भर भारत , कुशल भारत आदि योजना बनती है· लेकीन जब इसके लाभकारी चुनते समय सत्ता मे बैठे अपने हि सगे संबंधी को इसके लाभकारी बनाते है · अगर देश मे चुनाव हर पांच साल मे एक हि बार होते है तो जो समय इन युवाओ को मिलता है उसका सदुपयोग वह अपने और अपने परिवार के हित के बारे मे करेंगे · अपनी सोच को वह राष्ट्र निर्माण , राष्ट्र हित मे लगायेंगे ·चुनाव कि गंधी राजनीति से उभारकर साफ सुथरे चरित्र के युवा कि संख्या बढेगी · सामाजिक प्रश्नो को सरकार के सामने प्रस्तुत करणे मे अपनी उर्जा का उपयोग करेंगे · जनता के दुख दर्द को समझने मे अपना समय व्यतीत करेंगे· एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार अनेक प्रकार से युवा वर्ग कि सोच को सकारात्मक सोच मे बदलने हेतू आवश्यक है ·

F. सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने मे सक्षम :

चुनाव के दौरान सत्ता को प्राप्त करणे हेतू राजनीतिक दल और प्रत्याशी सभी लोकतांत्रिक मर्यादा को पार कर प्रचार करते है · जिसमे जाति , संप्रदाय ,धर्म ,चरित्र का हनन , पारिवारिक टीका ,अलोकतांत्रिक शब्द और भाषा का प्रयोग होता है · जिससे लोकतंत्र बदनाम और दागदाग होता है · लोकतंत्र पर होनेवाले यह अनैतिक प्रहार पिचले अनेक दशको से हो रहे है · जिसकारण लोकतंत्र और उसकी प्रणाली का राजनीतिक सामाजीकरण सही ढंग से नही होता है· चुनाव राजनेता और राजनीतिक दलो के लिए एक अवसर होता है · इस अवसर को सत्ता मे रुपांतरीत करणे हेतू किसी भी गैर मार्ग का उपयोग होता है ,चुनावी मर्यादा को लांघकर चुनाव प्रचार , सभा आदि का नियोजन होता है · अपराध का सहारा लेकर चुनाव जिते जाते है ·सामाजिक एकात्मता को भंग कर दंगे निर्माण करणे का काम चुनावी प्रचार सभा से होता है · जाति- जाति मे झगडे , धर्म मे दरार ,सांप्रदायिक चर्चा को बढावा , समाज मे एक दुसरे के प्रति द्वेष , पारिवारिक झगडे , परिवार मे दरार , कार्यकर्ता मे झगडे आदि जो सामाजिक पर्यावरण को बिगाड ने के काम होते है वह अधिकतर चुनाव मे हि होते है· चुनाव मे होनेवाले सभा , प्रचार से ध्वनी , वायू प्रदूषण होता है · चुनाव मे जीत हाशील करणे वाला प्रत्याशी बडी मात्रा मे फटाके बजाता है , गुलाल कि बौछार होती है, फुलो के माला के ढेर निर्माण होते है ·चुनाव के दौरान और बाद मे जो कचरा , कुडा सडक , हवा और पाणी के रूप मे निर्माण होता है · उसका विनियोग कैसे करे यह प्रशासन के सामने निर्माण होनेवाली बडी समस्या है · अधिकतर चुनाव इम्तिहान के काल मे होते है · चुनाव मे होणे वाला ध्वनी प्रदूषण छांत्र के पढाई मे बडी बाधा निर्माण करता है · इन सभी सामाजिक और पर्यावरणीय दोषो को देखते एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विचार सामने आया है वह सोचने योग्य है · इस विचार के कार्यन्वित होणे से देश निरंतर चुनाव के चक्कर से मुक्त होगा · सामाजिक समरसता को बढावा मिलेगा · पर्यावरण का जो प्रदूषण होता हे वह नही होगा ·

3. **वर्तमान सरकार कि गंभीरता** *:*

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मे काम करनेवाली सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे मे बडी हि गंभीरता से सोच रही है ·वर्तमान कोविड -19 आपदा का निर्माण नही होता तो यह सरकार अर्थसंकल्पीय सत्र मे इस विषय पर संसद मे बहस को जरूर छेडती· जून 2020 मे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमे राजनाथ सिंह कि अध्यक्षता मे एक समिती का निर्माण करणे के विचार पर सहमती बनी · भाजपा समेत उनके अन्य सहयोगी दल भी इस विचार के समर्थन मे है · नरेंद्र मोदीजी ने अपने साक्षात्कार मे अनेक जगह एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार किस प्रकार राष्ट्र और समाज के हित मे इस बात को स्पष्ट किया है ·इससे पैसा , मनुष्यबळ ,समय , साधन संपत्ती आदि कि बचत होगी · देश के राजनीतिक संस्कृती मे बदलाव होंगे · राष्ट्र और जन हित के बारे मे सोचने के लिए सभी को पर्याप्त समय मिलेगा · सकारत्मक राजनीति का माहोल निर्माण होगा · जो सभी के लिये अच्छा है · सरकार के इस सोच को राजनीति का रूप देणे का काम विपक्ष कि और से हो रहा है · विपक्ष भी इस विचार को खूल के विरोध नही कर रहा है· उनका भी यह मत है कि यह विचार अच्छा है लेकीन इस समय मे नही ·तो कूच विपक्ष इसे गैरसंवैधानिक मान कर लोकतंत्र के खिलाप मानते है · इससे संवैधानिक व्यवस्था का हनन होगा· एक व्यक्ती , एक नेता, एक दल , एक विचार को बढावा मिलेगा · प्रादेशिक राजनीतिक दल , स्थानीय विषय राष्ट्रीय राजनीति से बेदखल होंगे ·

एक राष्ट्र एक चुनाव उपाय एंव निष्कर्ष *:*

एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार तो अच्छा है लेकीन इसे कार्यन्वित करणे से पूर्व कूच संवैधानिक सुधार करणे होंगे· संवैधानिक धारा 83,85,172,174,356 और जनप्रतीनिधीत्व अधिनियम 1951 मे संशोधन करना होगा · मध्यावधी चुनाव कि प्रक्रिया का खात्मा करना होगा · इस विषय को जनता मे अधिक चर्चित कर उनकी राय को जानना चाहिए · लोकसभा चुनाव के समय पर यदी सभी राज्य अपनी विधानसभा को भंग कर लोकसभा के साथ चुनाव करते है तो भी यह व्यवस्था निर्माण होगी · उपरी सभी विषयो कि पूर्ती एक राष्ट्र एक चुनाव से होगी · इसलिये इस विषय पर देश के सभी राजनेता , राजनीतिक दलो के प्रतिनिधी , कर्मचारी , जनता , प्रशासनिक अधिकारी आदि को जनजागरण करना जरुरी है · जनता मे इस विषय को मिडिया , परिषद , विश्वविद्यालय ,महाविद्यालयो आदि के सहायता से ले जाना होगा· इस विचार से होनेवाले फायदे , नुकसान , निर्माण होनेवाली चुनोतीया इसके बारे मे संसद , राज्य विधानसभा सभी के पटल पर चर्चा होना जरुरी है · क्योंकी चर्चा लोकतंत्र कि निव को अधिक मजबूत करती है · एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक विषय , चुनाव आयोग कि समस्या को समझना होगा · एक राष्ट्र एक चुनाव से राजनीतिक संस्कृती , राजनीतिक सहभागीता , राजनीतिक विकास मे क्या बदलाव होंगे यह जनता और सभी वर्ग के लोगो को समझाने का काम सरकार को करना चाहीए·

संदर्भ साहित्य *:*

1. http://oneindiaonepeople.com/one-nation-one-election/
2. https://www.2thepoint.in/possibility-of-one-nation-one-election/
3. http://zeenews.india.com/india/bjps-push-for-one-nation-one-polls-is-a-gimmick-congress-2077288.html
4. http://www.indiafoundation.in/symposium-on-one-nation-one-election-2/
5. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/one-nation-one-poll-needs-many-legislation-cec-op-rawat/articleshow/62628484.cms
6. http://www.uniindia.com/call-for-one-nation-one-election-is-also-jumla-chidambaram/india/news/1122724.html
7. विधि आयोग का अहवाल
8. म्हाळगी प्रबोधनी का अहवाल
9. दैनिक लोकसत्ता